रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम014/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 फरवरी, 1991/8 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 27 फरवरी, 1991

संख्या 1-6/91-वि0 एस0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 2)

426-राजपत्र/91-27-2-91—1,182. मूल्य : 1 रुपया।

जो दिनांक 27 फरवरी, 1991 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो गया है। सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1991 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1991

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1991 है।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए 1,09,82,94,949 रुपये की और राशि जारी करना।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धनराशियां, जिनका योग 1,09,82,94,949 रुपये (एक अरब नौ करोड़, बयासी लाख, चौरानवे हजार और नौ सौ उनचास) हैं, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1990-91 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	1,000	—	1,000
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	4,000	—	4,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	16,26,000	18,86,000	35,12,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	1,45,35,000	—	1,45,35,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	93,52,771	—	93,52,771
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	5,10,000	—	5,10,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	—	1,13,727	1,13,727
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	11,14,86,000	2,000	11,14,88,000
		(पूंजी)	12,75,000	—	12,75,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	2,08,11,000	3,09,455	2,11,20,455
		(पूंजी)	51,00,000	20,221	51,20,221
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	33,00,000	1,45,000	34,45,000
		(पूंजी)	1,67,50,000	—	1,67,50,000
11	कृषि	(राजस्व)	1,99,97,000	12,044	2,00,09,044
		(पूंजी)	3,42,00,000	12,75,158	3,54,75,158
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(राजस्व)	8,20,03,000	87,000	8,20,90,000
		(पूंजी)	1,000	—	1,000
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	—	36,133	36,133
14	पशुपालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	1,10,96,000	—	1,10,96,000
		(पूंजी)	16,00,000	—	16,00,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	1,00,000	—	1,00,000
		(पूंजी)	31,85,000	—	31,85,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	1,58,83,923	10,33,267	1,69,17,190
		(पूंजी)	47,40,000	—	47,40,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	11,00,00,000	—	11,00,00,000
		(पूंजी)	30,00,000	1,69,81,000	1,99,81,000
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	34,16,000	—	34,16,000
		(पूंजी)	43,25,000	—	43,25,000
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	12,650	500	13,150
		(पूंजी)	26,14,000	—	26,14,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	2,62,91,000	—	2,62,91,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	26,21,99,000	—	26,21,99,000
22	खाद्य और भाण्डागारण	(राजस्व)	75,00,000	—	75,00,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	1,44,00,000	—	1,44,00,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
25	सड़क, जल परिवहन और नगर विमानन	(पूंजी)	100	—	100
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	10,00,000	—	10,00,000
28	जलपूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	16,43,36,000	—	16,43,36,000
		(पूंजी)	5,87,02,000	—	5,87,02,000
29	वित्त	(राजस्व)	10,00,000	1,000	10,01,000
		(पूंजी)	—	25,90,000	25,90,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	99,20,000	—	99,20,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	1,28,51,000	—	1,28,51,000
		(पूंजी)	3,46,79,000	—	3,46,79,000
		कुल जोड़	1,07,38,02,444	2,44,92,505	1,09,82,94,949
		(राजस्व)	89,37,11,344	36,26,126	89,73,37,470
		(पूंजी)	18,00,91,100	2,08,66,379	20,09,57,479

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

शान्ता कुमार,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
27 फरवरी, 1991.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाइल सं0 फिन-ए-सी-(2) 1/91]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1991 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 1991.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 1991

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1991.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 1991. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 1,09,82,94,949 (One hundred nine crores, eighty-two lakhs, ninty-four thousand and nine hundred fortynine rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1990-91 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule. Issue of a further sum of Rs. 1,09,82,94,949 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1990-91.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	1,000	—	1,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	4,000	—	4,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	16,26,000	18,86,000	35,12,000
4	General Administration	(Revenue)	1,45,35,000	—	1,45,35,000
5	Land Revenue	(Revenue)	93,52,771	—	93,52,771
6	Excise and Taxation	(Revenue)	5,10,000	—	5,10,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	—	1,13,727	1,13,727
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	11,14,86,000	2,000	11,14,88,000
		(Capital)	12,75,000	—	12,75,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	2,08,11,000	3,09,455	2,11,20,455
		(Capital)	51,00,000	20,221	51,20,221
10	Public Works	(Revenue)	33,00,000	1,45,000	34,45,000
		(Capital)	1,67,50,000	—	1,67,50,000
11	Agriculture	(Revenue)	1,99,97,000	12,044	2,00,09,044
		(Capital)	3,42,00,000	12,75,158	3,54,75,158
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	8,20,03,000	87,000	8,20,90,000
		(Capital)	1,000	—	1,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	—	36,133	36,133
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	1,10,96,000	—	1,10,96,000
		(Capital)	16,00,000	—	16,00,000
15	Fisheries	(Revenue)	1,00,000	—	1,00,000
		(Capital)	31,85,000	—	31,85,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	1,58,83,923	10,33,267	1,69,17,190
		(Capital)	47,40,000	—	47,40,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	11,00,00,000	—	11,00,00,000
		(Capital)	30,00,000	1,69,81,000	1,99,81,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	34,16,000	—	34,16,000
		(Capital)	43,25,000	—	43,25,000
19	Social Security and Welfare (including Nutrition)	(Revenue)	12,650	500	13,150
		(Capital)	26,14,000	—	26,14,000
20	Rural Development	(Revenue)	2,62,91,000	—	2,62,91,000
21	Co-operation	(Revenue)	26,21,99,000	—	26,21,99,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	75,00,000	—	75,00,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	1,44,00,000	—	1,44,00,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Capital)	100	—	100
26	Tourism and Hospitality Organisation	(Revenue)	10,00,000	—	10,00,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	16,43,36,000	—	16,43,36,000
		(Capital)	5,87,02,000	—	5,87,02,000
29	Finance	(Revenue)	10,00,000	1,000	10,01,000
		(Capital)	—	25,90,000	25,90,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	99,20,000	—	99,20,000
31	Tribal Development	(Revenue)	1,28,51,000	—	1,28,51,000
		(Capital)	3,46,79,000	—	3,46,79,000
	Grand Total ..		1,07,38,02,444	2,44,92,505	1,09,82,94,949
		(Revenue)	89,37,11,344	36,26,126	89,73,37,470
		(Capital)	18,00,91,100	2,08,66,379	20,09,57,479

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1990-91.

SHANTA KUMAR,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 27th February, 1991.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department, File No. Fin. A-C(2) 1/91]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the *Himachal Pradesh Appropriation* Bill, 1991, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित